>

Title: Need to expedite implementation of paddy procurement process in Punjab.

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का और सरकार का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पंजाब में अभी भी धान, जिसे पंजाब में हम चोना कहते हैं, उसकी खरीद को लेकर बहुत ही गम्भीर परिस्थिति बनी हुई है। केन्द्र सरकार ने हाल ही में धान की खरीद को लेकर जो मापदंड हैं, उनमें थोड़ी-बहुत छूट दी है, थोड़ी-बहुत ढील दी है। लेकिन इसके बावजूद जो खरीद है, वह बहुत ही धीमी गति से चल रही है। मंडियां भरी हुई हैं। आज एक महीना हो गया, किसान मंडियों में अपनी फसल को लेकर पड़ा हुआ है। वैसे तो जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है कि जो फसल की खरीद है, उसकी व्यवस्था ठीक तरह से की जाए, पर इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। वह इसलिए कि केन्द्र सरकार की जो एजेंसी है, फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसे भी बहुत सुचारू रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है।

जिस जिले का प्रतिनिधित्व मैं और माननीय सुखदेव सिंह जी करते हैं, परसों तक लुधियाना जिले में 12 लाख क्विंटल अनाज की खरीद हुई थी। उसमें से केवल 11 हजार क्विंटल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने खरीदा था। इस तरह की अगर परिस्थिति बनी रही, तो आने वाले समय में पंजाब में जो शांति है, वह भंग हो सकती है, परिस्थिति बिगड़ सकती है। यहां पर सरकार के बड़े वरिष्ठ मंत्री, माननीय मोइली जी, सलमान खुर्शीद साहब, श्रीप्रकाश जायसवाल जी बैठे हैं, मैं अभी माननीय कृषि मंत्री जी से भी मिला था तो उनसे भी मैंने आग्रह किया था कि इस परिस्थिति के ऊपर आप एक समिति बनाकर, इसकी जांच करके, इसके लिए जो भी करना आवश्यक हो वह करें। चाहे मोइश्चर के नॉर्म्स रिलेक्स करने आवश्यक हों, या डिसक्लेरेशन के नार्म्स रिलेक्स करने आवश्यक हों या और जो भी कदम उठाने जरूरी हों, वे उठाने चाहिए। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जो इस देश की खाद्य सुरक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर केन्द्र सरकार पंजाब के किसानों को जो उनका हक बनता है, उसे देने में विफल रहेगी, तो सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह देश और सूबे के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।